दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 21 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 261

महत्वपूर्ण एवं खास

नदियों के उफान को देखते हुए यूपी के 16 जिलों में बाढ़ अलर्ट

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के सोलह जिलों को आने वाले दिनों में बाढ़ के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर और मऊ शामिल हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने इन जिलों के प्रशासन को नोटिस जारी कर आने वाले दिनों में बाढ़ की आशंका जताई है। प्रभावित जिले रोहिणी, शारदा, घाघरा और राप्ती जैसी नदी के किनारे पर हैं, जिनमें जलस्तर नेपाल और यूपी के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बढ़ रहे हैं। रोहिणी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि शारदा, घाघरा और राप्ती खतरे के निशान के करीब हैं और भारी बारिश के कारण बढ़ने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। राहत आयुक्त ने कहा कि 14 जून से रिमोट सेंसिंग तस्वीरों में यह देखा गया था कि महाराजगंज में 28,581 हेक्टेयर और सिद्धार्थ नगर में 2,674 हेक्टेयर क्षेत्र पहले से ही पानी में हैं। इसके बाद से इन जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

दिल्ली में आया कम तीव्रता का भूकंप, कोई नुकसान नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आज 2.1 तीव्रता का कम तीव्रता वाला भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने यह जानकारी दी। भूकंप दोपहर 12.02 बजे इलाके में आया। हालांकि, किसी के तत्काल हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं थी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र 28.67 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.14 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था, जिसकी गहराई 7 किमी थी। दिल्ली पांच भूकंपीय क्षेत्रों में से चौथे के अंतर्गत आता है। ऐसा कम ही होता है कि दिल्ली भूकंप का केंद्र रहा हो। हालांकि, शहर में भूकंप तब महसूस होता है, जब मध्य एशिया या हिमालय की सीमा तक भूकंप आता है, जो एक उच्च भूकंपीय क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 1,200 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद इस साल फरवरी में भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई सेकंड के लिए तेज झटके महसूस किए गए थे।

अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन बेंगलुरु से गिरफ्तार

चेन्नई (आरएनएस)। अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को मलेशियाई महिला के साथ रेप और गर्भपात कराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एम मणिकंदन को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को चेन्नई सिटी पुलिस ने एक मलेशियाई महिला, जो एक्ट्रेस हैं, से कथित रूप से दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में बेंगलुरु में गिरफ्तार किया है। एम मणिकंदन मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार के गिरफ्तारी से बच रहे थे। इससे पहले बुधवार को मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जज अब्दुल कुद्दोस ने कथित आरोप की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है। जज ने कहा कि मामला एक पूर्व मंत्री की तरफ से किए गए कथित अपराध को लेकर है जो गंभीर प्रवृत्ति का है और प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने के योग्य भी है। याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। अगर जमानत दी जाती है, तो संभव है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गंभीर जांच से बचे। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री पर धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के अलावा, अड्यार ऑल वुमन पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी), 313 (महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात), 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने कहा कि वो पूर्व मंत्री मणिकंदन के साथ पिछले चार सालों से रिश्ते में थी, इस दौरान मणिकंदन शादी के बारे में बात करने से बचते रहे।

देश में संक्रमण व मौतों में आई गिरावट, 24 घंटे में 58,419 नए मामले, 1,576 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना की दूसरी लहर में 81 दिन बाद बड़ी राहत महसूस की गई, जब पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 60 हजार से कम देखने को मिले। हालांकि संक्रमण से होने वाली मौतें अभी डेढ़ हजार से ऊपर ही चल रही है। कोरोना संक्रमण का असर लगातार कम होने के कारण सक्रीय मरीजों में भी कमी आ रही है और ठीक होने वाले मरीजों की तादात तेजी से बढ़ने लगी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आकड़ों के अनुसार पिछले एक दिन के अंतराल में कोरोना के 58,419 नए मामले दर्ज किये गये, जिसके बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,98,81,965 हो गई है। इस प्रकार संक्रमण की दैनिक दर 3.22 प्रतिशत रह गई है। वहीं इस दौरान संक्रमण के कारण 1,576 और लोगों की मौत के बाद अब तक देश में संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,86,713 पहुंच गया है और यह मृत्यु दर 1.29 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 30,776 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है और अब देश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,87,66,009 हो गई है। इस तरह कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 96.27 प्रतिशत हो गई है। कोरोना की रफ्तार कम होने के कारण अब अस्पतालों व घरों में इलाज करा रहे सक्रीय मरीजों की संख्या में आ रही कमी के बाद यह संख्या 7,29,243 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.44 प्रतिशत है। जबकि भारत में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से ज्यादा हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार हो गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे।

❐ **देश में 39 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच-** देश में शनिवार को 18,11,446 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। इसके साथ ही अब तक महामारी का पता लगाने के लिए कुल 39,10,19,083 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं अब तक टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 27,66,93,572 खुराक लगाई जा चुकी हैं। मंत्रालय के अनुसार एक दिन पहले शनिवार को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीके की 20,49,101 पहली खुराक दी गई, जबकि 78,394 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान का का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से देश के 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 5,39,11,586 लोगों को पहली खुराक दी गई और कुल 12,23,196 को दूसरी खुराक दी गई है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई है।

❐ **राज्यों के पास वैक्सीन 3.06 करोड़ से अधिक टीके-** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3.06 करोड़ से अधिक कोविड-19 रोधी टीके उपलब्ध हैं और उन्हें अगले तीन दिनों में 24.53 लाख से अधिक टीके मिलेंगे। रविवार से सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार ने अभी तक 29,10,54,050 से अधिक टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसमें से बर्बाद हो चुके टीकों समेत कुल 26,04,19,412 टीकों की खपत हुई है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोविड-19 रोधी 3,06,34,638 टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि 24,53,080 और टीके भेजने की तैयारी है और अगले तीन दिनों में उन्हें ये मिल जाएंगे।

रेलवे ने एक सप्ताह में 33 लाख यात्रियों को कराया सफर

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले सात दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों से 32.56 लाख यात्रियों ने ट्रेन से सफर किया। रेलवे की जानकारी से संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना पाबंदियों में ढील के बाद प्रवासी कामगार फिर से अपने कार्यस्थलों की ओर लौट रहे हैं। रेलवे ने कहा कि इन यात्रियों ने लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से सफर किया जिनकी औसतन क्षमता 110.2 फीसदी थी। 11-17 जून के बीच इन यात्रियों ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहरों के लिए सफर किया। ये शहर रोजगार देने के लिए अग्रणी माने जाते हैं। रेलवे धीरे-धीरे अनलॉक हो रहे शहरों में कामगारों को लाने में मदद कर रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे शहरों से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलूरू और चेन्नई के लिए रेलवे मेल, एक्सप्रेस स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल और समर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। 18 जून को 983 मेल-एक्सप्रेस और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। यह आंकड़ा कोरोना काल से पहले के स्तर का 56 फीसदी है। इसके अलावा 1309 समर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। ये समर ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बंगलूरू और अन्य शहरों से जोड़ती हैं। अगले 10 दिनों 19 से 28 जून के दौरान करीब 29.15 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है। इन यात्रियों में प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के प्रसार के दौरान एक मई से 30 अगस्त के बीच रेलवे ने 63.15 लाख प्रवासी कामगारों को एक जगह से उनके गंतव्य तक पहुंचाया था।

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को राज्य स्तर पर तैयारियां

» ग्रामीण अंचलों को तैयार कर रहा है डीएवाई-एनआरएलएम

नई दिल्ली ,20 जून (आरएनएस)। देश कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य स्तर पर तैयारियों को तरजीह दी जा रही है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी कमर कस ली है। इसके लिए ग्रामीण अंचलों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 13,697.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

सूत्रों के अनुसार 4.04 लाख ग्राम संगठन गठित किए गए हैं। लोगों में कोरोना व टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए 30,709 क्लस्टर स्तरीय संघों का भी गठन किया गया है। यह सभंव किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), जिसकी मदद से ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा जा रहा है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत केंद्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से 17 जून 2021 तक 14 हजार मिशन स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें टीकाकरण, स्वच्छता से लेकर कोरोना प्रोटोकॉल तक शामिल हैं। इनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर 4.57 लाख एसएचजी सदस्यों को तैयार किया जा चुका है। सीडीओ कर्मचारी सामुदायिक संपर्क और 5.57 करोड़ वेलफेयर समूह सदस्यों को कोरोना संक्रमण के अभियान में जुड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा चुका है। यह सभी देश भर के 69.66 लाख स्वयं सहायता समूहों की 7.52 करोड़ महिलाओं के सक्षम समूहों से हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव और डीएवाई-एनआरएलएम की निदेशक नीता केजरीवाल ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में एसएचजी समूह की महिलाएं मास्क, सैनिटाइजर और हैंडवाश बनाकर ग्रामीणों और सरकारी विभागों को भी आपूर्ति कर रही हैं।

केंद्रीय कर्मियों को डीए व एरियर देने की तैयारी

» कैबिनेट सचिव के साथ 26 जून की बैठक में तय होगा बकाया जारी करने का तरीका

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 60 लाख रिटायर्ड लोगों को 18 माह से बंद डीए यानी महंगाई भत्ता व डीआर महंगाई राहत राशि मिलने जा रही है। इस बाबत वित्त मंत्रालय की ओर से फाइनल निर्णय ले लिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिकों का प्रतिनिधि समूह नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा।

प्रतिनिधि समूह का कहना है कि बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि बैठक में उस तरीके पर चर्चा होगी, जिसके आधार पर डीए की राशि और एरियर जारी किया जाएगा। बैठक का एजेंडा बता दिया गया है। कार्मिकों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कैबिनेट सचिव 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेंगे। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की हैं। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स, 18 माह से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बंद है। इसके अलावा दूसरे अन्य भत्ते जैसे एलटीसी पर भी रोक लगाई गई थी। कर्मियों का डीए, मई 2020 में 21 प्रतिशत था, एक जुलाई 2021 को वह 31 फीसदी हो गया है।

❐ **डीए, डीआर व एरियर एक साथ मिलने की संभावना-** शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार केंद्र को बता दिया गया है कि डीए, डीआर व एरियर एक साथ दिया जाए। यदि एरियर व दूसरे भत्ते एक साथ जारी करना संभव नहीं है तो उन्हें छोटे अंतराल की अवधि में दे दिया जाए। केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मी और पूर्व कर्मी, जनवरी 2020 से इन भत्तों का इंतजार कर रहे हैं। बतौर शिवगोपाल मिश्रा, सरकार का रुख सकारात्मक होना चाहिए, हमें ऐसी उम्मीद है। अब ऐसा कोई बड़ा कारण भी नजर नहीं आता, जिसके चलते सरकार ये कहे कि अभी कुछ दिन ठहर जाएं। कैबिनेट सचिव को पहले ही 18 महीने के एरियर के बारे में अवगत करा दिया गया है। जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक 24 प्रतिशत, दिसंबर 2020 से मई 2021 तक 28 प्रतिशत और जून 2021 से जुलाई 2021 तक डीए राशि का ग्राफ बढ़कर 31 फीसदी पर पहुंच गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयसीमा बढ़ा सकती है सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) की समयसीमा को मौजूदा के 30 जून से बढ़ाकर अगले साल मार्च तक करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय महामारी के बीच देश में नयी नियुक्तियों को प्रोत्साहन के लिए इस योजना की समयसीमा बढ़ा सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एबीआरवाई को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करने के अलावा दो साल के लिए नयी नियुक्तियों पर नियोक्ताओं के योगदान का भी भुगतान करती है। 22,810 करोड़ रुपये के व्यय की इस योजना के तहत एक अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक नियुक्त होने वाले कर्मचारी आएंगे।

सूत्रों ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एबीआरवाई की समयसीमा को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर मार्च, 2022 तक करने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव को जारी करने की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक इस योजना से 21 लाख नए नियुक्त कर्मचारियों को लाभ हुआ है। यह सरकार के 58.5 लाख के अनुमान से काफी कम है।

प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ की बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के संकेत

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की।

मोदी ने इस महीने की शुरुआत में विभिन्न मंत्रालयों के अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए विभिन्न समूहों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग पांच बैठकें की थीं। सूत्रों ने बताया कि शाह और सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी आज की बैठक में शामिल हुए। बैठक संबंधी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से पहले की कवायद हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मोदी ने इस महीने की शुरुआत में विभिन्न मंत्रालयों के अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए विभिन्न समूहों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग पांच बैठकें की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बैठक को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह बैठक हुई है। हालांकि किसी भी प्रकार का इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जम्मू-कश्मीर पर सरकार का फोकस

मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं बेहद ही ज्यादा हो गई है कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जरूर हुई होगी। हालांकि, जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का फ्यूचर प्लान क्या है इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि शाह और सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी आज की बैठक में शामिल हुए। बैठक संबंधी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से पहले की कवायद हो सकती है।

सर्वदलीय बैठक 24 को

वहीं राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है जिसमें तत्कालीन राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला केंद्र शासित प्रदेश के लिए भविष्य के कदम पर चर्चाके लिए प्रधानमंत्री आवास पर बैठक में आमंत्रित करने के लिए इन नेताओं से सम्पर्क किया। आमंत्रितों में चार पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कांफ्रेंस के फारुक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।